ीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं तो पहले ही महंगाई से जूझ रहे आम लोगों को
ज़ाम किए जाएंगे पर ऐसा कुछ न होने पर महिलाओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त
पंपों पर वाहन चालकों की कतारें लग गई।

ट में वृद्धि से उबाल

आम बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री
ोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने की
गाई से जूझ रहे आम लोगों में रोष व्याप्त हो
ने अपने घरों व दफ्तरों से निकलकर सीधे
र लिया। पिछले आठ-नौ माह से तेल की
हुई थी, लेकिन एक बार फिर से कीमत बढ़ने
राहत छीन ली। रविवार को होली मनाने से
हंगा पेट्रोल-डीजल खरीदने को मजबूर होना
ोल 47.79 रुपये और डीजल 34.48 रुपये

ल और डीजल में दाम बढ़ने से आम जन पर
ड़ेगा। दो जुलाई 2009 को पेट्रोल और डीजल
फरवरी 2010 दाम बढ़ने की बुरी खबर लेकर
ाल में केवल 2007 वर्ष ही ऐसा बीता जिस
दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई। वर्ष 2004 में

पेट्रोल के 33 रुपये प्रति लीटर था। उस समय डीजल 21 रुपये प्रति लीटर था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत गिरने के बाद केंद्र सरकार ने दो बार पेट्रोल-डीजल के दाम कम भी किए थे। दाम बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ़ने के आसार भी बन गए हैं। जिसमें सबसे अधिक प्रभाव किराया भाड़ा पर पड़ेगा। किराया भाड़ा अगर बढ़ा तो उसका सीधा असर आम आदमी के उपयोग की हर चीज पर पड़ेगा। खाद्य पदार्थ से लेकर दैनिक उपयोग की हर एक वस्तु के दाम बढ़ जाएंगे। सबसे अधिक असर उन वस्तुओं पर पड़ेगा जो दूर दराज से क्षेत्रों से पहुंचती है। पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी से उद्योग जगत पर भी असर होगा। प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाने के कारण दाम भी बढ़ेंगे। इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लिए पेट्रोल-डीजल की बढ़ोतरी का संकट लेकर आया है। गुड़गांव पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके जैन ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों के निर्देश के अनुसार दाम तय होंगे। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल में 2.70 रुपये और डीजल में 2.50 रुपये की बढ़ोतरी है।

दिक्कत

ाज से मिलेगा महंगा पेट्रोल
ौर डीजल, पेट्रोल पंपों पर
ा में शाम से ही लंबी-लंबी
लाइनें लगी रहीं। पंपों पर
ाइक सवारों को 200 रुपये
और कारों को 500
रुपये से ज्यादा का पेट्रोल
नहीं मिल रहा था।

कब-कब बढ़े डीजल के दाम

दिनांक	दाम	बढ़ोतरी
16 मई 2004	22 रुपये 74 पैसे	1 रुपया
21 जून 2005	28 रुपये 45 पैसे	6 रुपये
01 जून 2006	30 रुपये 47 पैसे	2 रुपये
14 फरवरी 2007	31 रुपये 76 पैसे	2 रुपये
05 जून 2008	34 रुपये 45 पैसे	3 रुपये
02 जुलाई 2009	31 रुपये 38 पैसे	2 रुपये
26 फरवरी 2010	34 रुपये 48 पैसे	2.50 रुपये

स्वागत

र्स एंड इंडस्ट्री

के महासचिव एसके
अच्छा है। इसमें सभी
कृषि क्षेत्र को भी काफी

स्वागत किया है। पेट्रोल
है कि प्रोडक्शन कॉस्ट

आयकर स्लैब को लेकर निराशा की स्थिति

गुड़गांव। आम बजट मे आयकर स्लैब न बढ़ने आम आदमी में निराशा का माहौल है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद लोग आयकर का स्लैब दो लाख से अधिक होने की उम्मीद कर रहे थे। कई टैक्स कंसलटेंटों एवं जानकारों ने इसे पूंजीपतियों का बजट करार दिया है।

टैक्सेसन के वकील एमसी चतुर्वेदी के अनुसार 25 हजार रुपये प्रति माह तक की आय वालों के लिए इस बजट में कोई लाभ नहीं है। बल्कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जबकि इससे ऊपर की आमदनी वालों को राहत दी गई है। जाहिर है इस दायरे में सभी मध्यम वर्गीय परिवार आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बजट में मोटी तनख्वाह वालों को राहत देने का प्रयास किया गया है। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से निराशा ही हाथ लगी है।

कहीं मिली तारीफ तो कहीं टूटी उम्मीदें

हर सेक्टर की मिली-जुली प्रतिक्रिया रही बजट को लेकर

गुड़गांव। आखिरकार केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के बजट के पिटारे में क्या है इसका पता सबको लग गया। यह बजट किसी को आशा तो किसी को निराशा प्रदान कर गया। सभी सेक्टरों से बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया हासिल हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन सभी पूरी नहीं हो पाईं। इस सेक्टर के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह रही कि इसे इंफ्रास्ट्रक्टर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया। वहीं, आईटी सेक्टर के लिए यह काफी अच्छा रहा। नैस्कॉम ने इसका स्वागत किया है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बजट को अत्यंत निराशाजनक बताया। गुड़गांव के अधिकतर उद्यमियों ने बजट की प्रशंसा की तो किसी ने इस बजट को उद्योग और आम लोगों के लिए बेकार बताया।

रहेजा डेवलपर्स लि. के एमडी नवीन रहेजा

रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के एमडी नवीन रहेजा ने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को रियल एस्टेट सेक्टर के लिए मिलाजुला बताया। फिर भी उन्होंने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक है। उन्होंने स्टिमुलस पैकेज नहीं वापस लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को काफी फायदा होगा। उन्हें निराशा है कि सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया।

अंसल के प्रेसीडेंट एनके सहगल

रियल एस्टेट कंपनी अंसल के प्रेसीडेंट एनके सहगल ने बजट की प्रशंसा की कहा

यह बजट देश के विकास के लिए काफी हितकर है। उन्होंने वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया। 80 1बी के तहत टैक्स इक्जेंप्शन की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाना रियल एस्ट्रेट, सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। यह मार्च 2011 तक बढ़ा दी गई है। राजीव गांधी आवास योजना की भी उन्होंने तारीफ की।

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल

अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी) के चेयरमैन प्रेमल उदानी ने यूनियन बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सिर्फ खर्च संतुलित करने और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने पर ही ध्यान दिया है। उन्होंने अपने बजट के माध्यम से अल्पकालीन और दूरगामी रोडमैप तैयार करने में सफल नहीं रहे। यूनियन बजट से लेबल-इंसेंटिव अपैरल इंडस्ट्री को खास लाभ नहीं हुआ। हालांकि प्रेमल उदानी ने सरकार निर्यात क्रेडिट पर पहल का स्वागत किया है।

नैस्कॉम ने किया स्वागत

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैस्कॉम) ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। नैस्कॉम का कहना है कि यह बजट देश के संतुलित विकास के लिए सक्षम है। नैस्कॉम के चेयरमैन प्रमोद भसीन ने कहा कि यह बजट विशेष आर्थिक क्षेत्रों लिए काफी सकारात्मक है। बजट में सर्विस टेक्स रिफंड और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और राजकोषीय घाटे को संतुलित करने का प्रयास किया गया है।